

भारत में अभिरिक्षा में यातना

प्रलिस के लयि:

[अनुसूचति जाति \(SC\)](#), [अनुच्छेद 21](#), [अनुच्छेद 20\(1\)](#), [अनुच्छेद 20\(3\)](#), [मानवाधकारिों की सार्वभौमकि घोषणा \(UDHR\)](#), [नागरकि और राजनीतकि अधकारिों पर अंतरराष्टरीय वाचा](#), [आरथकि, सामाजकि एवं सांसकृतकि अधकारिों पर अंतरराष्टरीय वाचा](#), [UNCAT](#), [NHRC](#) ।

मेन्स के लयि:

भारत में अभिरिक्षा में यातना की स्थति, अभिरिक्षा में यातना को रोकने हेतु आवश्यक उपाय ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यौं?

तमलिनाडु में हुई अभिरिक्षा में मृत्यु ने एक बार फरि अभिरिक्षा में यातना के मुद्दे को प्रमुखता से उजागर कर दया है ।

अभरिक्षा में यातना क्या है?

- **परचिय:** अभरिक्षा/हरिसत में यातना (Custodial Torture) का तात्पर्य उन व्यक्तियों को शारीरकि या मानसकि पीडा पहुँचाने से है, जो पुलसि या कसिी अन्य प्राधकिरण की अभरिक्षा में होते हैं ।
 - यह मानवाधकारिों और मानवीय गरमा का गंभीर उल्लंघन है तथा प्रायः अभरिक्षा में मृत्यु का कारण बनता है — यानी जब कोई व्यक्ति अभरिक्षा में रहते हुए मर जाता है ।
- **अभरिक्षा में यातना के प्रकार:**
 - शारीरकि यातना (Physical Torture): मारपीट, बजिली के झटके देना, दम घोटना, यौन हरसा, जबरन तनावपूर्ण स्थति में रखना और चकितिसकीय देखभाल से वंचति करना ।
 - मानसकि प्रताडना (Psychological Torture): धमकियाँ, अपमान, नींद से वंचति करना, एकांत कारावास और मृत्युदंड की धमकी (Mock executions) ।
 - अत्यधिक दबाव डालकर नरिद्धों से अपराध स्वीकार करवाना ।
- **भारत में अभरिक्षा में यातना:**
 - अभरिक्षा में मृत्यु: वर्ष 2016 से 2022 के बीच, तमलिनाडु (दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक) ने 490 अभरिक्षा में मृत्यु की रपिरट की, जबकि पूरे देश में यह आँकड़ा 11,656 रहा । उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2,630 मृत्यु दर्ज की गई ।
 - नवारक नरिध कानून (Preventive Detention Law) का दुरुपयोग: वर्ष 2022 में, तमलिनाडु ने नवारक कानूनों के तहत 2,129 लोगों को अभरिक्षा में लिया, जो पूरे भारत की कुल संख्या का लगभग आधा है ।
 - [अनुसूचति जातियों \(SC\)](#) पर अत्यधिक यातना: तमलिनाडु में अनुसूचति जातियों की जनसंख्या केवल 20% होने के बावजूद अभरिक्षा में लयि गए लोगों में उनका अनुपात 38.5% रहा, जो उनके खिलाफ अभरिक्षा में अत्यधिक हरसा को दर्शाता है ।

अभरिक्षा में यातना के वरिद्ध संवैधानकि और वधकि सुरक्षा उपाय क्या हैं?

संवैधानकि प्रावधान

- **अनुच्छेद 14:** अनुच्छेद 14 वधकि समक्ष समता सुनश्चिति करता है तथा यह पुष्टिकरता है कि वधिप्रवर्तन एजेंसियों या अधकारियों सहति कोई भी वधिसे ऊपर नहीं है ।
- **अनुच्छेद 21:** [अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधकार](#) की गारंटी देता है, जसिमें यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या

अपमानजनक व्यवहार या दंड से स्वतंत्रता भी शामिल है।

- **अनुच्छेद 20(1): अनुच्छेद 20(1)** यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो उस समय वर्धि के तहत अपराध नहीं था जब वह कथि गया था। यह अत्यधिक या भूतलक्षी दंड को प्रतर्बिधति करता है।
- **अनुच्छेद 20(3): अनुच्छेद 20(3)** किसी भी व्यक्ति को स्वयं के वरिद्ध साक्ष्य देने के लिये वविश कथि जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी आरोपी से यातना या दबाव द्वारा स्वीकारोक्ति नहीं करवाई जा सके।

वधिकि प्रावधान

- **भारतीय न्याय संहति (2023) की धारा 120:** यह उन व्यक्तियों को दंडति करती है जो किसी संस्वीकृतिा जानकारी प्राप्त करने के लिये जानबूझकर हसिा या प्रपीडन के माध्यम से चोट या गंभीर चोट पहुँचाते हैं।
- **भारतीय नागरकि सुरक्षा संहति (BNSS, 2023) की धारा 35:** यह प्रावधान करता है कि गरिफ्तारी और अभरिक्षा केवल वैध कारणों तथा प्रलेखति प्रक्रिया के अनुसार ही की जानी चाहिये।
- **भारतीय साक्ष्य अधनियम (2023) की धारा 22:** यह ऐसे सभी स्वीकारोक्तियों को अमान्य घोषति करता है जो उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीडन या किसी वादे के तहत की गई हों।

अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:** यह प्रावधान करता है कि कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कथि जाए तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएँ **नागरकि एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR)** के तहत सुरक्षति रहें (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है)।
- **मानवाधिकारों की सार्वभौमकि घोषणा (1948):** यह व्यक्तियों को यातना, क्रूर व्यवहार और जबरन गायब कथि जाने (Enforced disappearances) से संरक्षण प्रदान करती है तथा सम्मान व सुरक्षा के अधिकार की गारंटी देती है।

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: [यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन \(UNCAT\), 1984](#)

अभरिक्षा में यातना पर अंकुश लगाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वशिष्ट यातना-वरीधी कानून का अभाव:** भारत ने वर्ष 1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर तो कथि हैं, लेकिन अब तक उसे अनुमोदति नहीं कथि है।
 - हालाँकि मानवाधिकार संरक्षण अधनियम, 1993 जैसे कुछ कानूनों में यातना को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधति कथि गया है, लेकिन यातना को अपराध घोषति करने वाला कोई स्वतंत्र, वशिष्ट कानून नहीं है। इससे वर्तमान प्रावधान अस्पष्ट, अपर्याप्त और कड़ी सज़ा से रहति रहते हैं।
- **कमज़ोर प्रवर्तन और दंड से मुक्ति:** वर्ष 2017 से 2022 के बीच अभरिक्षा में मृत्यु के 345 न्यायकि जाँच मामलों में केवल 123 गरिफ्तारियाँ और 79 चार्जशीट दाखलि हुईं, लेकिन एक भी दोषसदिधि (Conviction) नहीं हुई।
 - अवैध अभरिक्षा, यातना या मृत्यु से जुड़े 74 मानवाधिकार उल्लंघन मामलों में पुलसि के वरिद्ध केवल 3 दोषसदिधि दर्ज की गई।
- **अधभारति संस्थाएँ:** मानवाधिकार आयोग (NHRC/SHRC) के पास बाध्यकारी शक्तियों का अभाव है और वे सरकारी वतित पोषण पर नरिभर हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमति हो जाती है।
 - जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ (130% क्षमता पर) और स्वतंत्र नगरिनी की कमी अनेक राज्यों में प्रभावी पुलसि शकियायत प्राधिकरण का अभाव, ऐसे हालात उत्पन्न करते हैं जो उत्पीडन और अमानवीय व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।
- **पीडतियों में प्रतहिसिा का भय:** पीडति प्रायः प्रताडना की शकियायत दर्ज कराने से बचते हैं क्योंकि उन्हें प्रतहिसिा का भय, कानूनी सहायता का अभाव और शकियायत दर्ज करते समय धमकियों का सामना करना पड़ता है।
 - हाशयि पर मौजूद समूह (दलति, अल्पसंख्यक, आदविसी) वशिष रूप से असुरक्षति हैं क्योंकि पीडति संरक्षण और मुआवज़ा तंत्र अपर्याप्त हैं।
- **न्यायकि और प्रणालीगत वफिलताएँ:** लंबी न्यायकि प्रक्रियाएँ, अत्यधिक भारग्रस्त न्यायालयों, साक्षयियों को डराए जाने और त्वरति न्यायालयों की अपर्याप्तता के कारण अभरिक्षा में मृत्यु के मामलों में न्याय में देरी होती है।
 - इसके अतरिकित, डी.के. बसु दशानरिदेशों (1996) जनिमें गरिफ्तारी मेमो, चकित्सकीय परीक्षण और कानूनी सहायता की अनविर्यता शामिल है - का कमज़ोर अनुपालन, साथ ही मजसि्ट्रेटी जाँचों की अक्षमता, प्रणालीगत वफिलता और जवाबदेही लागू करने या पुलसि व्यवस्था में सुधार लाने की राजनीतिक इच्छाशक्तिकी कमी को दर्शाता है।

अभरिक्षा में यातना रोकने के लिये मुख्य सफिरशियें

- **भारत का वधिआयोग:** अपनी 273वीं रिपोर्ट (2017) में भारत के वधिआयोग ने UNCAT 1984, की पुष्टिकरने तथा उसके प्रावधानों को लागू करने हेतु एक वशिष्ट कानून बनाने की सफिरशि की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यातना को दंडनीय अपराध घोषति करना अत्यंत आवश्यक है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/custodial-torture-in-india>

